नईदुनिया

भोपाल, 30 जून 2026

संपादकीय

# दलाल कौन ? कांग्रेस के घर में छिड़ी जंग

**मध्य प्रदेश** *की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि आखिर दलाल कौन है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली में प्रेसवार्ता कर मोहन यादव सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हैं और आरोप लगाते हैं कि उज्जैन में वीर भारत न्यास को एक रुपये में 500 करोड़ रुपये की जमीन दे दी गई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार श्रीराम तिवारी ट्रस्ट में हैं और यह खुला घोटाला है। लेकिन अगले ही दिन उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उसी सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि ट्रस्ट निजी नहीं, बल्कि सरकारी है, इसलिए जमीन देना गलत नहीं है।*

*एक ही पार्टी के दो बड़े चेहरे आमने-सामने हैं। एक सरकार को चोर बता रहा है, दूसरा उसी सरकार को साधु बता रहा है। जनता पूछ रही है कि भरोसा किस पर करे—पटवारी पर या दिग्विजय पर, कांग्रेस पर या भाजपा पर? दिग्विजय सिंह ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कमलनाथ स्वयं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। अब सवाल यह है कि यह सफाई है या पटवारी के आरोपों पर सवाल? उन्होंने आगे कहा कि देश में दलालों की कमी नहीं है, जो झूठे आरोप लगाकर पैसा वसूलते हैं। यह बयान सीधे पटवारी के आरोपों की धार को कमजोर करता है।*

*अब सवाल उठता है कि दलाल कौन है? पटवारी, जो आरोप लगा रहे हैं, या वे लोग, जिनकी ओर दिग्विजय सिंह बिना नाम लिए इशारा कर रहे हैं? भाजपा को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि कांग्रेस खुद अपने नेताओं के बयानों से घिरी हुई है। मोहन यादव सरकार पर हमला करने से पहले कांग्रेस को अपने घर में झांकना चाहिए। पटवारी कहते हैं कि जमीन घोटाला हुआ है, जबकि दिग्विजय कहते हैं कि सब नियमों के तहत हुआ है। ऐसे में कार्यकर्ता किसकी बात माने?*

*असल में यह लड़ाई जमीन की नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति की नजर आती है। जीतू पटवारी नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार को आक्रामक ढंग से घेरना चाहते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह अनुभवी नेता हैं। उनके बयान ने भाजपा को राहत दी और पटवारी के अभियान की धार कम कर दी।*

*वीर भारत न्यास की जमीन का सच क्या है, यह तो पूरी फाइल सामने आने पर ही स्पष्ट होगा। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को खुद ही उलझा दिया है। यदि पटवारी के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें अपने आरोपों पर कायम रहना चाहिए। वहीं यदि दिग्विजय सिंह के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो अध्यक्ष के पास नहीं हैं, तो उन्हें पहले पार्टी मंच पर रखना चाहिए। मीडिया में परस्पर विरोधी बयान केवल भ्रम पैदा करते हैं और सत्ता पक्ष को राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं।*

*सरकार को भी चाहिए कि वह पूरी फाइल सार्वजनिक करे और बताए कि जमीन किस नियम के तहत, किस उद्देश्य से दी गई तथा ट्रस्ट में कौन-कौन शामिल है। इससे जनता स्वयं तय कर सकेगी कि मामला घोटाले का है या केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का। कांग्रेस नेतृत्व को भी अब स्पष्ट निर्णय लेना होगा, क्योंकि घर की लड़ाई लंबी चली तो बाहर की लड़ाई जीतना और कठिन हो जाएगा।*

आजकल

### डिजिटल डकैती पर लगेगा ताला

# आहा! ऐप से पुलिस का संवाद होगा फुलप्रूफ

**मध्यप्रदेश** पुलिस अब साइबर अपराधियों की डिजिटल डकैती को रोकने के लिए खुद मैदान में उतर आई है। पुलिस ने अपना सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका नाम आहा! ऐप रखा गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जूम और गूगल मीट जैसे विदेशी ऐप पर पुलिस की गोपनीय बैठकें खतरे में पड़ रही थीं। अभी तक एटीएस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच जैसे संवेदनशील ऑपरेशन की रणनीति भी इन्हीं ऐप पर बनती थी। लेकिन इन ऐप के सर्वर विदेश में हैं और लिंक लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार अनजान लोग बैठक में शामिल हो जाते हैं, जिससे पुलिस की पूरी योजना अपराधियों तक पहुंच सकती है। आहा! ऐप इसी डिजिटल सेंधमारी को रोकने के लिए लाया गया है।

आहा! ऐप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसका नियंत्रण पूरी तरह पुलिस के पास रहेगा। इसका सर्वर, डेटा और लॉगिन सिस्टम सब पुलिस मुख्यालय की निगरानी में होगा। बाहरी व्यक्ति इसमें झांक भी नहीं सकेगा। केवल अधिकृत अधिकारी ही इससे जुड़ पाएंगे और हर गतिविधि का रिकॉर्ड दर्ज होगा। इससे थाना स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक की हर रणनीति गोपनीय रहेगी।

पुलिस का कहना है कि आहा! ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड स्टोरेज, सुरक्षित चैट और ऑनलाइन बैठक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेंज, जोन, जिला और थाने तक के अधिकारी एक क्लिक पर जुड़ सकेंगे। प्रशिक्षण, समीक्षा और आपात समन्वय के लिए अब किसी बाहरी ऐप पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।

सिर्फ प्लेटफॉर्म बना देना काफी नहीं है। हर थाने में इंटरनेट और सिस्टम दुरुस्त करना होगा, हर पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण देना होगा और समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट भी करना होगा। यदि आहा! ऐप इस कसौटी पर खरा उतरता है, तो यह न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश की पुलिस के लिए एक मिसाल बन सकता है।

# 8 हजार जनशिक्षक बदलेंगे सरकारी स्कलों की दिशा

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और पढ़ाई की सतत निगरानी के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग अब लगभग 8 हजार वीएसी जनशिक्षकों को मैदान में उतारने जा रहा है। इन जनशिक्षकों का मुख्य कार्य स्कूलों में जाकर कक्षाओं का नियमित निरीक्षण करना, शिक्षकों की उपस्थिति देखना, बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करना और शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करना होगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। अभिभावक निजी स्कूलों की ओर रुख करते रहे हैं और सरकारी स्कूलों की छवि कमजोर पड़ती रही है। अब विभाग का मानना है कि यदि स्कूल स्तर पर ही सख्त और नियमित निगरानी हो जाए तो शिक्षा की दिशा बदल सकती है।

वीएसी का अर्थ है विद्यालय आकलन समन्वयक और जनशिक्षक का अर्थ है समाज से जुड़ा वह व्यक्ति, जो शिक्षा को जनआंदोलन बनाकर आगे बढ़ाए। प्रत्येक विकासखंड में इन जनशिक्षकों की तैनाती होगी। एक विकासखंड में 21 विद्यालयों पर एक जनशिक्षक की व्यवस्था रखी गई है। इस हिसाब से प्रदेशभर में लगभग 8 हजार जनशिक्षक मैदान में नजर आएंगे। ये जनशिक्षक प्रतिदिन स्कूल जाएंगे। वहां शिक्षक समय पर आए हैं या नहीं, यह देखेंगे। बच्चे कक्षा में सक्रिय हैं या नहीं, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है या नहीं तथा मध्याह्न भोजन, पोशाक, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जनशिक्षक मोबाइल ऐप या रजिस्टर में जानकारी दर्ज करेंगे और उसकी रिपोर्ट सीधे जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारियों को भेजेंगे।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह निगरानी ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से ऊपर की ओर होगी। पहले निरीक्षण के लिए अधिकारी साल में एक-दो बार स्कूल जाते थे और औपचारिकता पूरी कर लौट आते थे। अब हर दिन हर स्कूल पर किसी न किसी जनशिक्षक की नजर रहेगी। इससे शिक्षकों में अनुशासन आएगा और वे कक्षा में लापरवाही नहीं बरत पाएंगे। साथ ही यदि किसी स्कूल में संसाधनों की कमी है या कोई शिक्षक बीमार है तो उसकी जानकारी तुरंत उच्च स्तर तक पहुंचेगी और समाधान भी जल्दी निकलेगा।

जनशिक्षक केवल निरीक्षक नहीं होंगे, बल्कि मार्गदर्शक भी बनेंगे। यदि कोई नया शिक्षक पढ़ाने में कमजोर है तो जनशिक्षक उसे पढ़ाने के तरीके सुझाएंगे। यदि बच्चे किसी विषय में कमजोर हैं तो अतिरिक्त अभ्यास की योजना बनाएंगे। इस प्रकार यह व्यवस्था दंडात्मक नहीं, बल्कि सहयोगात्मक होगी।

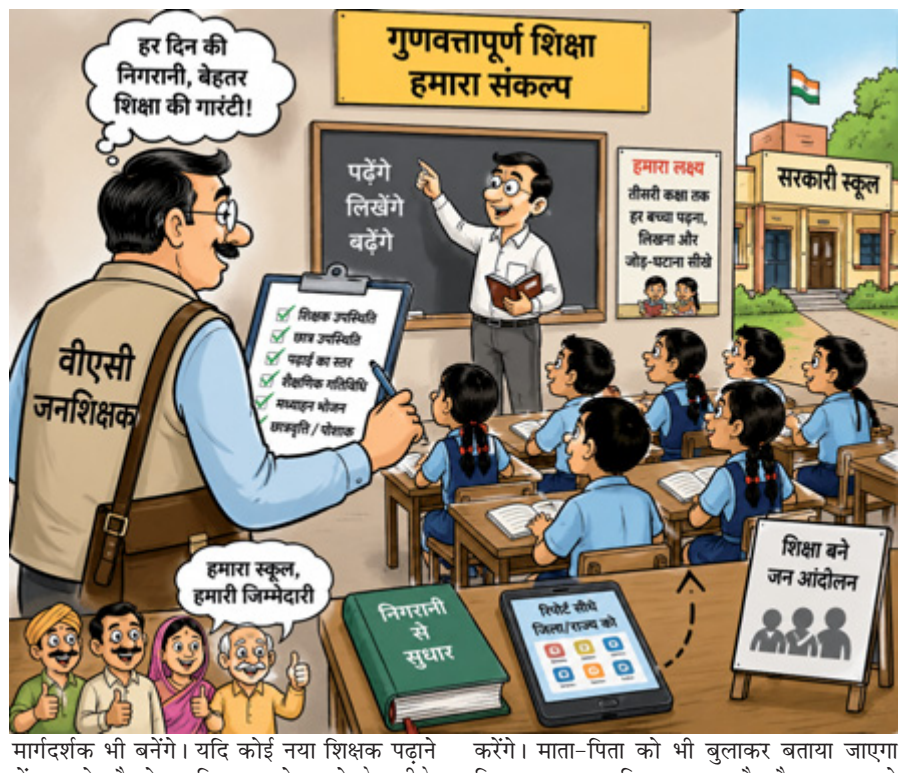


सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी और बच्चों के सीखने की धीमी गति रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल ऐसे हैं, जहां एक शिक्षक पांच कक्षाओं को संभालता है। ऐसे में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं हो पाता। जनशिक्षक की उपस्थिति से शिक्षक पर सकारात्मक दबाव बढ़ेगा और वह अपनी तैयारी बेहतर करेगा। वहीं कमजोर बच्चों की पहचान कर उनके लिए विशेष कक्षाएं लगाने में भी मदद मिलेगी। विभाग का लक्ष्य है कि तीसरी कक्षा तक हर बच्चा पढ़ना, लिखना और जोड़-घटाना सीख जाए, क्योंकि आधार मजबूत होगा तो आगे की पढ़ाई भी आसान होगी। इसके लिए जनशिक्षक हर महीने बच्चों का आकलन करेंगे और प्रगति चार्ट तैयार करेंगे। माता-पिता को भी बुलाकर बताया जाएगा कि उनका बच्चा किस स्तर पर है और घर पर उसे किस प्रकार का अभ्यास कराया जाए।

जनशिक्षकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। स्थानीय शिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे क्षेत्र की भाषा और संस्कृति को समझ सकें तथा बच्चों से बेहतर जुड़ सकें। चयनित जनशिक्षकों को पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आकलन की विधियां, पाठ योजना की जांच, सीखने के स्तर को मापने के उपकरण और बच्चों से संवाद करने की कला सिखाई जाएगी। उन्हें तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे फोटो, वीडियो और आंकड़े तुरंत अपलोड कर सकें। इससे रिपोर्ट में पारदर्शिता आएगी और फर्जी रिपोर्ट का खतरा कम होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनशिक्षक शिक्षकों पर हावी नहीं होंगे, बल्कि दोनों मिलकर स्कूल को बेहतर बनाने का काम करेंगे।

चुनौतियां भी सामने होंगी। सबसे बड़ी चुनौती जनशिक्षकों की जवाबदेही तय करना है। यदि वे स्वयं समय पर स्कूल नहीं पहुंचे या रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरतें तो पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। इसके लिए उनके कार्य का भी नियमित मूल्यांकन होना चाहिए और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दूसरी चुनौती संसाधनों की है। 8 हजार लोगों को मानदेय, प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराना एक बड़ा खर्च है, लेकिन शिक्षा पर किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि एक शिक्षित बच्चा ही भविष्य में देश की प्रगति में योगदान देता है। तीसरी चुनौती शिक्षकों और जनशिक्षकों के बीच समन्वय की है। यदि दोनों के बीच टकराव हुआ तो स्कूल का वातावरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जनशिक्षक मित्र हैं, आलोचक नहीं।

अभिभावकों और समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब जनशिक्षक स्कूल आएं तो ग्राम पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य भी उनका सहयोग करें। वे देखें कि जनशिक्षक निष्पक्षता से काम कर रहे हैं या नहीं और शिक्षक भी पूरा सहयोग दे रहे हैं या नहीं। यदि गांव का व्यक्ति ही शिक्षा की निगरानी करेगा तो स्कूल गांव से कटेगा नहीं, बल्कि गांव का गौरव बनेगा। निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा तभी संभव है, जब सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में अनुशासन और पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो। यह तभी होगा, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से आकर देखे कि स्कूल में वास्तव में क्या हो रहा है।

लगभग 8 हजार वीएसी जनशिक्षकों की तैनाती सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय लिख सकती है। यह कदम केवल निरीक्षण का नहीं, बल्कि शिक्षा को जनआंदोलन बनाने का है। जब मैदान में उतरकर कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूछेगा कि आज बच्चों ने क्या सीखा, तो शिक्षक भी पूरी तैयारी के साथ कक्षा में आएगा और बच्चे भी पढ़ाई में अधिक रुचि लेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता एक दिन में नहीं सुधरती, लेकिन निरंतर निगरानी और ईमानदार प्रयास से निश्चित रूप से सुधर सकती है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू हुई तो आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों के परिणाम बेहतर होंगे, ड्रॉपआउट दर घटेगी और अभिभावकों का विश्वास भी वापस लौटेगा, क्योंकि देश का भविष्य उन्हीं बच्चों के हाथों में है, जो आज सरकारी स्कूलों की बेंच पर बैठे हैं, और 8 हजार जनशिक्षक उसी भविष्य को संवारने का दायित्व निभाएंगे।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

# देशी उत्पादों का जलवा : लस्सी-छाछ ने पछाड़ा कोल्ड ड्रिंक को

इस साल की रिकॉर्डतोड़ गर्मी ने देश के 1.1 लाख करोड़ रुपये के सॉफ्ट ड्रिंक्स बाजार का गणित ही बदल दिया है। किराना दुकानों के फ्रिज और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोल्ड ड्रिंक्स के साथ छाछ, लस्सी और प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ने जबरदस्त जगह बना ली है। यह बदलाव खासकर युवा उपभोक्ताओं और शहरी घरों में दिख रहा है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बजाय हेल्थ और प्रोटीन-आधारित डेयरी बेवरेज को तरजीह दे रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देशी उत्पादों का जलवा अब लौट आया है और विदेशी कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की बादशाहत को सीधी चुनौती मिल रही है।

आईएमएआरसी के आंकड़ों के अनुसार, सॉफ्ट ड्रिंक्स का मौजूदा बाजार 111.81 हजार करोड़ रुपये का है, जो सालाना 4.64 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। वहीं, लस्सी का बाजार 5.60 हजार करोड़ से बढ़कर 24.57 हजार करोड़ और छाछ का बाजार 19.33 हजार करोड़ से बढ़कर 101.18 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। लस्सी की सालाना वृद्धि दर 16.96 प्रतिशत और छाछ की 18.16 प्रतिशत है। यानी देसी बेवरेज की बिक्री चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स की ग्रोथ एकल अंक में सिमट गई है। मदर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयतीर्थ चारी के मुताबिक, इस सीजन लस्सी और छाछ जैसे डेयरी उत्पादों ने 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है।

लस्सी और छाछ की बिक्री बढ़ने की सबसे बड़ी वजह टैक्स का अंतर है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी है, जबकि डेयरी बेवरेज पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इस 35 प्रतिशत के अंतर के कारण डेयरी कंपनियां 10 रुपये का उत्पाद भी आसानी से बेच पा रही हैं। दूसरी वजह हेल्थ और न्यूट्रिशन है। कोविड के बाद उपभोक्ता स्वाद के साथ सेहत भी चाहते हैं। लस्सी, छाछ, प्रोबायोटिक और लो-शुगर पेय हेल्दी विकल्प बन गए हैं। युवा वर्ग अब अधिक शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर से दूरी बना रहा है। तीसरी वजह मॉडर्न और ट्रेडिशनल का संगम है। हाइजेनिक पैकेजिंग के साथ कोकम, जलजीरा, आम पना और छाछ जैसे पेयों की बाजार में दोबारा एंट्री हुई है। अमूल, मदर डेयरी, पराग और हेरिटेज फूड्स जैसी कंपनियां पुदीना छाछ, प्रोबायोटिक छाछ और प्रोटीन लस्सी जैसे नए वैरिएंट 10 रुपये की शुरुआती कीमत पर ला रही हैं।

हेरिटेज फूड्स के सीईओ श्रीदीप केसवन का कहना है कि कंपनी के राजस्व में डेयरी बेवरेज का योगदान पिछले तीन वर्षों में दोगुना हो चुका है। पराग मिल्क फूड्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षाली शाह के अनुसार, भारत की पैकेज्ड फूड एवं बेवरेज इंडस्ट्री 9.51 लाख करोड़ रुपये की है, जो 2030 तक 14.27 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी। डेयरी ड्रिंक्स बाजार 2031 तक 4.23 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसी कारण कंपनियां प्रोटीन, हेल्थ और वेलनेस आधारित उत्पादों पर फोकस कर रही हैं। पराग के इस कारोबार में सालाना आधार पर 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मदर डेयरी ने अवतार प्रोटीन कोल्ड कॉफी लॉन्च की है, जिसमें 15 ग्राम प्रोटीन है और जिसे स्वाद व पोषण दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

शहरी युवा अब ब्रांड की चमक से ज्यादा न्यूट्रिशन लेबल पढ़ता है। जिम जाने वाले युवाओं के लिए 20 ग्राम प्रोटीन वाली लस्सी, कोल्ड ड्रिंक से बेहतर विकल्प बन रही है। ऑफिस जाने वाले लोग दोपहर में भारी-भरकम कोल्ड ड्रिंक की जगह छाछ को चुन रहे हैं, क्योंकि इससे एसिडिटी नहीं होती और पेट भी हल्का रहता है। गर्मी में नमक और जीरे वाली छाछ शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करती है। यही वजह है कि कॉलेज कैंटीन से लेकर कॉरपोरेट कैफेटेरिया तक अब देशी बेवरेज की मांग बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर भी लस्सी और छाछ को 'कूल ड्रिंक' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। रील्स और शॉर्ट्स में 'देसी स्वैग' का नया ट्रेंड बन गया है।

देशी बेवरेज की मांग बढ़ने से सीधा फायदा डेयरी किसानों को हो रहा है। दूध की खपत बढ़ने से गांवों में पशुपालकों की आय बढ़ी है। सहकारी समितियां अब छाछ, लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क की यूनिट लगा रही हैं। इससे गांवों में ही रोजगार पैदा हो रहा है और शहरों की ओर पलायन भी घट रहा है। एक लीटर छाछ बनाने में करीब 400 मिलीलीटर दूध लगता है। इस तरह डेयरी सेक्टर की वृद्धि तेज हुई है। सरकार की डेयरी विकास योजनाओं को भी इससे बल मिला है। विदेशी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड अब नई रणनीति बना रहे हैं। शुगर-फ्री वैरिएंट लॉन्च किए जा रहे हैं और स्थानीय फ्लेवर जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन 40 प्रतिशत जीएसटी और बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस के चलते उनकी राह आसान नहीं है। कुछ कंपनियां अब जूस और डेयरी सेगमेंट में भी उतर रही हैं, ताकि बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रख सकें। हालांकि भारतीय स्वाद और भरोसा जीतना उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि लस्सी और छाछ पीढ़ियों से घर-घर में बनती रही हैं और अब वही स्वाद हाइजेनिक पैकेजिंग में उपलब्ध है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ट्रेंड अस्थायी नहीं है। आने वाले पांच वर्षों में डेयरी बेवरेज का बाजार कोल्ड ड्रिंक के बराबर पहुंच सकता है। फूड सेफ्टी मानकों और कोल्ड चेन के मजबूत होने से टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी इसकी पहुंच बढ़ेगी। स्टार्टअप भी नवाचार कर रहे हैं। बाजरे की छाछ, रागी की लस्सी और ओट्स आधारित ड्रिंक्स जैसे उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। सरकार यदि डेयरी उत्पादों पर जीएसटी 5 प्रतिशत ही बनाए रखती है और प्रोसेसिंग यूनिट को सब्सिडी देती है, तो भारत वैश्विक डेयरी बेवरेज हब बन सकता है।

देशी उत्पादों का जलवा फिर से लौट आया है। कोल्ड ड्रिंक के प्रति भारतीयों की घटती पसंद ने साबित कर दिया है कि स्वाद, सेहत और जेब—इन तीनों के संतुलन पर ही बाजार टिकता है। लस्सी और छाछ ने सिर्फ गर्मी ही नहीं मिटाई, बल्कि विदेशी ब्रांड्स के वर्चस्व को भी चुनौती दे दी है। यह आत्मनिर्भर भारत की सशक्त तस्वीर है, जहां दादी-नानी के नुस्खे अब आधुनिक पैकेजिंग में दुनिया जीतने की ओर बढ़ रहे हैं।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

**लस्सी और छाछ की बिक्री बढ़ने की सबसे बड़ी वजह टैक्स का अंतर है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी है, जबकि डेयरी बेवरेज पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इस 35 प्रतिशत के अंतर के कारण डेयरी कंपनियां 10 रुपये का उत्पाद भी आसानी से बेच पा रही हैं। दूसरी वजह हेल्थ और न्यूट्रिशन है। कोविड के बाद उपभोक्ता स्वाद के साथ सेहत भी चाहते हैं।**

# देश में विदेशी कैंपस, फीस में 40% की बचत

**उच्च शिक्षा का नया दौर, अब डिग्री सबके दायरे में**

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। अब विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री के लिए लाखों रुपये खर्च कर सात समंदर पार जाने की मजबूरी खत्म हो रही है। ऑक्सफोर्ड, येल, इलिनॉयस टेक, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और अन्य बड़े नाम अब भारत में ही अपने कैंपस खोल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में कैंपस शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। इनमें से अधिकांश कैंपस का पहला बैच अगस्त से शुरू होना तय है। पहले बैच में प्रत्येक कैंपस में 200 से 250 छात्रों से शुरुआत होगी और अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 1,000 से 1,200 तक ले जाने का लक्ष्य है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा छात्रों और अभिभावकों को फीस के मोर्चे पर मिलेगा। विदेश में पढ़ाई का कुल खर्च अब 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इसकी वजह साफ है। छात्र को रहने-खाने, वीजा, यात्रा और बीमा पर होने वाला भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। कोर्स की संरचना ऐसी रखी गई है कि छात्र को एक से दो सेमेस्टर विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी की पढ़ाई भारत स्थित कैंपस में होगी। इससे डिग्री तो विदेशी विश्वविद्यालय की मिलेगी, लेकिन जेब पर बोझ घटेगा। साथ ही जॉब नेटवर्क भी मजबूत होगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अपने वैश्विक इंडस्ट्री टाई-अप का लाभ भारतीय कैंपस के छात्रों को भी देंगे।

पिछले पांच वर्षों में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। 2020 में 6.9 लाख छात्र विदेश गए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 13.3 लाख तक पहुंच गया। 2025 में 16 लाख से अधिक छात्रों के विदेश जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत को सबसे बड़े शिक्षा बाजार के रूप में पहचाना है। यूजीसी द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देने के बाद यह रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब इन विश्वविद्यालयों को भारतीय छात्रों तक पहुंचने के लिए मेलबर्न या लंदन जाने की जरूरत नहीं है। विश्वस्तरीय शिक्षा अब भारत में उपलब्ध होगी। कैंपस में वही फैकल्टी, वही पाठ्यक्रम और वही डिग्री मिलेगी, जो मूल कैंपस में मिलती है। दूसरा लाभ लागत में कटौती का है। अमेरिका या ब्रिटेन में ग्रेजुएशन पर औसतन 80 लाख से 1.2 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जबकि भारत में यही डिग्री 45 से 60 लाख रुपये में पूरी हो सकेगी। तीसरा लाभ सैंडविच प्रोग्राम का है। छात्र तीन वर्ष के कोर्स में छह महीने से एक वर्ष तक विदेशी कैंपस में पढ़ सकेगा। इससे उसे अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर भी मिलेगा और खर्च भी नियंत्रित रहेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारतीय छात्रों के लिए पात्रता को भी अपेक्षाकृत लचीला रखा है। 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत और ग्रेजुएशन में 55 से 70 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। बोर्ड के अंकों की अनिवार्यता में भी कुछ छूट दी गई है। 85 प्रतिशत अंक होने पर आईईएलटीएस देने की आवश्यकता नहीं होगी। पाठ्यक्रम, परीक्षा और ग्रेडिंग पूरी तरह मूल कैंपस जैसी होगी। इसका मतलब है कि छात्र को वही गुणवत्ता मिलेगी, लेकिन प्रवेश की दौड़ अपेक्षाकृत आसान होगी।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जा चुके हैं। इनमें ब्रिटेन की यॉर्क और एबरडीन, अमेरिका की इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के अलावा गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी दो विश्वविद्यालयों ने कैंपस के लिए जगह ले ली है। 10,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, जो इस मॉडल की लोकप्रियता को दर्शाते हैं।

विदेशी कैंपस के आने से भारतीय निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों पर गुणवत्ता सुधारने का दबाव बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा से फीस का ढांचा भी अधिक तर्कसंगत होगा। वहीं भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए विदेशी संस्थानों के साथ रिसर्च और फैकल्टी एक्सचेंज के नए अवसर खुलेंगे। इंडस्ट्री से जुड़े कोर्स, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शिक्षण व्यवस्था अब सामान्य अपेक्षा बन जाएंगी। जो संस्थान समय के साथ नहीं बदलेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवेश लेने से पहले तीन बातों की जरूर जांच करनी चाहिए। पहली, यूजीसी से मान्यता पत्र। दूसरी, डिग्री का प्रारूप—यह सुनिश्चित कर लें कि डिग्री मूल कैंपस से जारी होगी या भारतीय कैंपस के नाम से। तीसरी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। चूंकि ये कैंपस नए हैं, इसलिए पहले दो-तीन बैच के प्लेसमेंट पर नजर रखना जरूरी होगा। केवल ब्रांड के नाम पर निर्णय न लें, बल्कि कोर्स कंटेंट और फैकल्टी प्रोफाइल का भी मूल्यांकन करें।

सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंचे। विदेशी विश्वविद्यालयों की मौजूदगी से न केवल छात्रों का पलायन रुकेगा, बल्कि भारत एजुकेशन हब के रूप में भी उभरेगा। अफ्रीका, मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के छात्र भी भारतीय कैंपस का रुख कर सकते हैं। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। यह बदलाव केवल फीस का नहीं, बल्कि सोच का है। अब विदेशी डिग्री सिर्फ संपन्न परिवारों के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगी। मध्यम वर्ग का छात्र भी येल या ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित डिग्री का सपना भारत में रहकर पूरा कर सकेगा। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण ही नए भारत की असली पहचान है और विदेशी कैंपस का आगमन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले दो वर्षों में तस्वीर और स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि डिग्री अब अपेक्षाकृत सस्ती होगी और अधिक लोगों की पहुंच में होगी।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**